लेटर्स पेटेंट अपील

माननीय मुख्य न्यायधीश मेहर सिंह व माननीय न्यायधीश आर.एस. नरूला के समक्ष

मोहन लाल और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

भगवती प्रसाद और अन्य-प्रतिवादी

1996 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 84
मार्च 11, 1970

पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम (1952) - नियम 11(2), 40(बी) और 63(1) (सी)- दोहरे सदस्यीय नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव - आरक्षित सीट के लिए उम्मीदवार द्वारा अपने अनुसूचित जाति के सदस्य होने की निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित घोषणा के बिना नामांकन पत्र दाखिल करना -नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र - ऐसे नामांकन पत्र - क्या वैध हैं - दोहरे सदस्य में आरक्षित सीट से लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्र को स्वीकार करने के आदेश को रद्द करना नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र-निर्वाचित उम्मीदवार का अकेले चुनाव-क्या रद्द किया जाए-निर्वाचन क्षेत्र का पूरा चुनाव-क्या अवैध हो जाता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम, 1952 के नियम 11 (2) की आवश्यकता यह है कि दो सदस्यीय नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र के साथ उसके अनुसूचित जाति का सदस्य होने की घोषणा होनी चाहिए। उम्मीदवार की घोषणा आवश्यक रूप से नामांकन पत्र पर ही होनी जरुरी नही है और यह नियम का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि नियम के तहत आवश्यक उम्मीदवार की घोषणा एक अलग कागज पर निहित है जो नामांकन पत्र के साथ है। लेकिन नियम की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि नामांकन पत्र के साथ जो घोषणा होनी चाहिए उसे स्वयं निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि घोषणा स्वयं किसी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है लेकिन नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्राधिकारी का एक अलग प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, तो यह उक्त नियम की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार घोषणा का सत्यापन न करना नियम 63 (1) (सी) में उपयोग की जाने वाली उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक भौतिक अनियमितता है और ऐसा नामांकन पत्र मान्य नहीं है।

(पैरा 6)

यह माना गया कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 'एक चुनाव' है और इसकी तुलना दो अलग-अलग चुनावों से नहीं की जा सकती है। नियमों के नियम 40 (बी) में निहित प्रावधान का प्रभाव यह है कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने वालों में से सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले व्यक्तियों को आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है और शेष उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों को, चाहे वो सामान्य सीट या आरक्षित सीट से हों, सामान्य सीट के लिए चुनाव घोषित करने के लिए एक साथ विचार करना होता है। दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के हिस्से को बनाए रखना असंभव है जब तक कि इसके परिणाम घोषित करने का तरीका नियम 40 (बी) में प्रदान किए गए पैटर्न पर है। इसलिए यदि एक दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्र को

स्वीकार करने का आदेश रद्द कर दिया जाता है, तो उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र का पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाता है, न कि अकेले लौटे उम्मीदवार के चुनाव का।

(पैरा 16 और 21)

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली द्वारा *1968* की सिविल रिट संख्या *1347* में पारित दिनांक *24* जनवरी, *1969* के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड *10* के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

एच. एल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एस.सी. सिब्बल,अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।
नंद लाल ढींगरा और कुलवंत राय, अधिवक्ता, केवल प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

प्रलय

1. नरूला, जे० - इस लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय की मांग करने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दो सदस्यीय नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्र को स्वीकार करने के आदेश को रद्द करने पर उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र का पूरा चुनाव या विशेष रूप से लौटे उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाता है। यह प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है :-

2. मोहन लाल और माता दीन अपीलकर्ताओं के साथ-साथ भगवती प्रसाद और अन्य, प्रतिवादी नंबर 1 से 20, ने वार्ड नंबर 1 से चुनाव के लिए अपना नामांकन रेवाड़ी नगर समिति को दाखिल किया। मोहन लाल अपीलकर्ता और उदमी राम, प्रतिवादी संख्या 7 और चार अन्य उम्मीदवारों ने आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा। नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 1952 (इसके बाद चुनाव नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 40(ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसके लिए इस निर्णय के बाद के भाग में विस्तृत संदर्भ दिया जाएगा, मोहन लाल अपीलकर्ता को आरक्षित सीट से और माता दीन अपीलकर्ता को सामान्य सीट से निर्वाचित घोषित किया गया। हालांकि वार्ड से चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका मांगे लाल रस्तौगी प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष दायर की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय में अप्रैल, 1968 में भगवती प्रसाद (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें निर्वाचन अधिकारी के 5 फरवरी, 1968 के आदेश (अनुलग्नक 'ए') को रद्द करने के लिए कहा गया था, जिसमें मोहन लाल अपीलकर्ता के नामांकन के खिलाफ उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था के साथ ही उपायुक्त गुड़गांव के दिनांक 15 फरवरी 1968 (अनुलग्नक 'बी') के आदेश को भी खारिज कर दिया गया था जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ भगवती प्रसाद प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज और अपीलकर्ता नंबर 1 के नामांकन पत्र की वैधता को बरकरार रखा गया था। रिट याचिका में आगे प्रार्थना की गई थी कि कोई अन्य निर्देश या आदेश जो इस न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त माना जा सकता है उसे भी जारी किया जा सकता है। मोहन लाल के नामांकन पत्र की वैधता पर दो आपत्तियां विद्वान, एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी गयी, जिसमें से केवल एक ही सफल हुई और यह केवल उस आपत्ति के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की शुद्धता है जिस पर श्री एस सी सिब्बल, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील, द्वारा हमारे समक्ष हमला किया गया था। वह आपत्ति इस आशय की थी कि अपीलकर्ता संख्या 1 का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता था क्योंकि यह चुनाव नियमों के नियम 11 के उप-नियम (2) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता था, जैसा कि मोहन लाल की घोषणा थी कि वह जटिया चमार जाति का सदस्य था जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति है, नामांकन पत्र पर किसी भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस मामले में तथ्यात्मक रूप से जो हुआ था, वह यह था। निर्धारित घोषणा नामांकन पत्र पर ही अनुमोदित की गई थी और मोहन लाल (अपीलक र्ता) द्वारा

विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। इसे किसी भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। तथापि, घोषणा पत्र के साथ उप-विभागीय अधिकारी, रेवाड़ी,जो स्वीकार्य रूप से निर्धारित प्राधिकारी थे, द्वारा एक अलग प्रमाण पत्र भी दिया गया था, जो निम्नलिखित था -

" यह प्रमाणित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के रेवाड़ी गांव , तहसील रेवाड़ी, जिला गुड़गांव के श्री मोहन लाल पुत्र श्री देव करण, जाटिया चमार समुदाय से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1959 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री मोहन लाल सामान्यतः हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में रहते हैं। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार, रेवाड़ी से उचित सत्यापन के बाद जारी किया गया है।"

दिनांक: 24 जनवरी, 1968

3. अपीलकर्ता मोहन लाल की ओर से रिट याचिका का विरोध किया गया था। 7 जुलाई, 1968 को उनके रिटर्न में विवाद में आपत्ति के संबंध में कहा गया था कि चुनाव नियमों के नियम 11 के उप-नियम (2) का काफी हद तक अनुपालन किया गया था, जब नामांकन पत्र के साथ एक नियमित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था और वह प्रमाणपत्र मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया था।अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान के पैराग्राफ़ 6 (ii) में कहा कि रिटर्निंग अधिकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और इसलिए, उन्होंने उन्हें नामांकन काग़ज पर प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए नहीं कहा और यह कि यदि निर्वाचन अधिकारी ने अपीलकर्ता को ऐसा करने के लिए कहा होता, तो पेपर वहां पर ही फिर पूरा हो गया होता और सत्यापन की औपचारिकता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में स्वयं की गई होती। अंत में, यह कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप एक तकनीकी दोष होता है, को अपीलकर्ता या उसके हित को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

4. अपील के तहत अपने फैसले में माननीय तुली, जे० ने कहा कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ (माननीय मुख्य न्यायाधीश और तुली, जे खुद) द्वारा बिहारी लाल बनाम उपायुक्त, अमृतसर और अन्य, *(1)* [1]मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर और फतेह सिंह बनाम श्री के. सी. ग्रोवर और अन्य (2) मामले में पहले की खंडपीठ (फलशॉ, सी० जे० और ग्रोवर, जे०) के फैसले को ध्यान में रखते हुए), मोहन लाल अपीलकर्ता का नामांकन पत्र चुनाव नियमों के नियम 11 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था और इसलिए अस्वीकार किया जा सकता था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, 24 जनवरी, 1969 के एकल न्यायाधीश के फैसले द्वारा रिटर्निंग अधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकरण के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया था और दोनों अपीलकर्ताओं के साथ-साथ रेवाड़ी नगर समिति के वार्ड नंबर 1 से 20 तक के चुनाव को रद्द कर दिया गया था व पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

5. दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से पेश श्री सिब्बल ने इस अपील में केवल दो प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले एकल न्यायाधीश के आदेश की शुद्धता पर इसके गुण-दोष के आधार पर हमला किया है, जहां तक यह मोहन लाल के नामांकन पत्र की वैधता को बरकरार रखने वाले रिटर्निंग अधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों की वैधता से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित तथ्य, जिनका विस्तृत संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, विवाद में नहीं हैं। निर्वाचन नियमावली का नियम 11(2) निम्नलिखित शर्तों में है :-

"एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, किसी भी उम्मीदवार को उस सीट

---

[1](1)) आई.एल.आर. (1969) I Pb. &. Hr. 604.

(2) 1964 के सीडब्ल्यू 927 का फैसला 1 अक्टूबर, 1964 को किया गया था।

को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके नामांकन पत्र के साथ उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण द्वारा सत्यापित घोषणा न हो कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके लिए सीट इतनी आरक्षित है और घोषणा उस विशेष जाति को निर्दिष्ट करती है जिसका उम्मीदवार सदस्य है।

6. जिस वार्ड के चुनाव में हम चिंतित हैं, वह निश्चित रूप से एक दो- सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था। जब तक पहला अपीलकर्ता नियम 11 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तब तक उसे आरक्षित सीट के लिए चुने जाने के योग्य नहीं माना जा सकता है। नियम की आवश्यकता यह है कि नामांकन पत्र एक घोषणा के साथ होना चाहिए। इससे पता चलता है कि उम्मीदवार की घोषणा नामांकन पत्र पर ही होनी जरूरी नहीं है और यह नियम का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि नियम के तहत आवश्यक उम्मीदवार की घोषणा एक अलग कागज पर निहित है जो नामांकन पत्र के साथ है। लेकिन नियम की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि नामांकन पत्र के साथ जो घोषणा होनी चाहिए उसे स्वयं निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इस मामले में यह विवादित नहीं है कि घोषणा स्वयं किसी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी बल्कि नामांकन पत्र के साथ 24 जनवरी, 1968 को निर्धारित प्राधिकारी का एक अलग प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। हम श्री सिब्बल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस मामले में जो कुछ हुआ है, उसे संबंधित नियम की अपेक्षाओं के पर्याप्त अनुपालन के बराबर माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वकील चाहते हैं कि हम यह मानें कि घोषणा का सत्यापन न करना उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर भौतिक अनियमितता नहीं है जैसा कि चुनाव नियमों के नियम 63 (1) (सी) में उपयोग किया गया है।

7. एस. एस. दुलत और ए. एन. ग्रोवर, जे. जे. द्वारा निर्धारित गुरदीप सिंह बनाम श्री गुरमेज सिंह *(* 3)[2]मामले में अमृतसर सदर निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा की आरक्षित सीट के चुनाव से संबंधित निर्णय में करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा, चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 1951 के अधिनियम के तहत निर्धारित उचित घोषणा के अभाव में, जांच अधिकारी द्वारा कुछ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था।। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सवाल यह नहीं था कि उम्मीदवार किसी विशेष जाति से संबंधित थे या नहीं, बल्कि यह था कि क्या 1951 के अधिनियम द्वारा आवश्यक उचित घोषणा वास्तव में की गई थी और यदि नहीं तो क्या उस घोषणा में दोष पर्याप्त चरित्र का था। ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि नामांकन पत्र के साथ दायर प्रमाण पत्र का कोई परिणाम नहीं था और आगे कहा कि नामांकन में अपेक्षित विवरण देने में चूक पर्याप्त चरित्र का दोष था जिसे तथ्य के साक्ष्य को देखकर ठीक नहीं किया जा सकता था और इसलिए रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्र को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखते हुए, डिवीजन बेंच ने बृजेंद्रलाल गुप्ता और अन्य बनाम ज्वालाप्रसाद और अन्य (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप की कुछ टिप्पणियों के संदर्भ के बाद ,1951 अधिनियम की धारा 116-ए के तहत इस अदालत को प्राथमिकता देते हुए इसके खिलाफ अपील को खारिज कर दिया इस आशय से कि ऐसे मामलों में यह देखा जाना चाहिए कि वैधानिक घोषणा उचित रूप में दायर की गई है या नहीं और यह नहीं कि क्या उम्मीदवार ने वास्तव में कुछ योग्यता प्राप्त की थी। 1951 के अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) के वाक्यांशविज्ञान को बहुत महत्व दिया गया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव नियमों के नियम 11 (2) की तरह, एक उम्मीदवार को आरक्षित सीट को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि अपेक्षित घोषणा नहीं दी गई हो। विद्वान न्यायाधीशों ने इस संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"यह फॉर्म का मामला है, लेकिन आवश्यकता वैधानिक है, और उप-धारा (2) में संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां संसद ने यह कहने का विकल्प चुना है कि

---

(3) 1963 के एफएओ 3-ई का निर्णय 8 अप्रेल, 1963 को लिया गया।

इस तरह की घोषणा के बिना उम्मीदवार को योग्य नहीं माना जाएगा।"

पीठ ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि गुरदीप सिंह के मामले (3) में शामिल नामांकन पत्रों में दोष पर्याप्त प्रकृति का था और चुनाव न्यायाधिकरण नामांकन पत्रों को अस्वीकार करना उचित था।

8. फ़तह सिंह बनाम श्री के० सी० ग्रोवर((2)[3] के मामलें में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से घोषणा की गई थी और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए नामांकन फॉर्म का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया गया था, हालांकि उम्मीदवार **द्वारा कागज का एक** अलग टुकड़ा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा ,कमोबेश उसी तर्ज पर जो सत्यापन के निर्धारित प्रपत्र में पाया जाता है, सत्यापन किया गया था।

संबंधित नियम के पर्याप्त अनुपालन के बारे में तर्क को गुरदीप सिंह के मामले (3) (सुप्रा) में पहले के फैसले के अधिकार पर खारिज कर दिया गया था।

9. अंतिम मामला जो इस बिंदु पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है वह बिहारी लाल बनाम डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर और अन्य, (1) में माननीय मुख्य न्यायधीश और तुली, जे. द्वारा लिया गया निर्णय है। यह मामला अमृतसर नगर पालिका के दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से संबंधित है। निर्वाचन अधिकारी ने आरक्षित सीट के लिए सभी तीन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिए थे कि उनके साथ चुनाव नियमों के नियम 11 (2) के अनुसार किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उनकी घोषणाओं का सत्यापन नहीं किया गया था। चुनाव नियमों के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी अमृतसर के उपायुक्त ने हालांकि बिहारी लाल का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया। चुनाव के परिणामस्वरूप, बिहारी लाल को आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। तब इस न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उनके चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया गया था। सरकारिया, जे. ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, उपायुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने बिहारी लाल के नामांकन पत्र को सही ढंग से खारिज कर दिया था। उस फैसले के खिलाफ एक अपील में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि बिहारी लाल का नामांकन पत्र दो आधारों पर दोषपूर्ण था, अर्थात्, (i) बिहारी लाल की घोषणा को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और एक अलग पेपर पर सत्यापन नियम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, क्योंकि मजिस्ट्रेट या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, जो सत्यापित करना था, वह गंभीर प्रतिज्ञान पर उसके समक्ष की गई उम्मीदवार की घोषणा थी, और इस तथ्य को अलग से सत्यापित नहीं करना था कि उम्मीदवार एक निश्चित जाति का सदस्य था; और (ii) कि निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र उसकी स्वयं की गवाही पर होना चाहिए न कि किसी और के सत्यापन पर। उस मामले में निर्धारित प्राधिकारी ने श्री करनैल सिंह, एम.एल.ए. और श्री गुरदीप सिंह की गवाही या सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया था कि बिहारी लाल अनुसूचित जाति से संबंधित है। डिवीजन बेंच ने माना कि निर्धारित प्राधिकारी ने अपनी घोषणा अपने व्यक्तिगत ज्ञान से नहीं की थी, न ही उन्होंने कहा था कि बिहारी लाल ने उनके सामने ऐसी घोषणा की थी, और इसलिए, नामांकन पत्र अमान्य था और इसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। हम बिहारी लाल के मामले के प्रासंगिक तथ्यों के बीच और इस मामले में जहां तक विवाद के गुण-दोष का सवाल है, कोई अंतर नहीं पा रहे हैं।हमारे लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि बिहारी लाल के मामले (1) का फैसला गलत तरीके से किया गया है।

---

(3) ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1049.

10. श्री सिब्बल ने इस संबंध में चुनाव नियमों के नियम 11 (1) (पंजाब सरकार, स्थानीय सरकार संहिता, खंड 1 के पृष्ठ 549 पर मुद्रित फॉर्म 1) के तहत नामांकन पत्र के निर्धारित फॉर्म का उल्लेख किया, जिसमें वह प्रपत्र जिसमें मजिस्ट्रेट या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना है, घोषणा पत्र के ठीक नीचे (पृष्ठ 550 पर) मुद्रित किया जाता है, जिस पर एक उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है। इससे क्या सलाह लेने की मांग की गई, यह मेरी समझ से परे है। यदि कुछ है, तो यह पहले की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुसरण किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

11. मोहन लाल अपीलकर्ता की ओर से कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है, उन्हें हमारे द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

12. यह मुझे दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है जिसे श्री सिब्बल ने अधिक गंभीरता से उठाया है। उनका निवेदन यह था कि माता दीन के चुनाव को रद्द करने के लिए कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई थी और किसी भी घटना में, चुनाव नियमों के विशेष वाक्यांशों को ध्यान में रखते हुए, यह अकेले लौटे हुए उम्मीदवार का चुनाव है जिसे इस निष्कर्ष पर रद्द किया जा सकता था कि उसका नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया था, लेकिन उसी निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य सीट पर माता दीन का चुनाव उस कारण से प्रभावित नहीं हो सकता था। वकील ने इस उद्देश्य के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इस फैसले में 1951 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के संबंधित प्रावधान पर ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि चुनाव नियमों के नियम 63(1) (सी) की भाषा 1956 में संशोधित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 (1) की भाषा से मेल खाती है।यह उस धारा के संशोधन से पहले की भाषा के विपरीत है। निर्वाचन नियमावली का नियम 63(1) (c) निम्नलिखित "शर्तों" में है:-
"आयोग की राय में, इन नियमों में इसके बाद किए गए प्रावधान को छोड़कर-
(a) * * * * *
(b) ** * * * *
(c) कोई भौतिक अनियमितता हुई है;
(d) * * * * *
आयोग रिपोर्ट करेगा कि लौटाए गए उम्मीदवार का चुनाव शून्य माना जाएगा।

13. 1956 में इसके संशोधन से पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 (1) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: –
"यदि ट्रिब्यूनल की राय है-
(a)* * * *
(b) * * * *
(c) कि चुनाव का परिणाम किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है;
ट्रिब्यूनल चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करे।"
असंशोधित धारा 100 (एल) (सी) का अर्थ लगाते हुए और एक ऐसे मामले पर इसके प्रभाव से निपटने के दौरान जहां दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए सदस्यों में से एक का चुनाव नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के कारण रद्द होने के लिए उत्तरदायी पाया गया था, यह सुरेंद्र नाथ खोसला और एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा एस दलीप सिंह और अन्य (5)[4], मामले में निर्धारित किया गया था जो इस प्रकार हैं: –

---

(5) ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 242=1957 एस.सी.जे 162.

"अंत में यह आग्रह किया गया कि यह मानते हुए कि जहां तक सामान्य सीट का संबंध है, ट्रिब्यूनल का चुनाव को शून्य घोषित करना उचित था, तो पूरे चुनाव को रद्द करने का कोई कारण नहीं था और इसलिए दूसरे अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था।लेकिन धारा 100 में प्रावधान है कि यदि ट्रिब्यूनल की राय थी, जैसा कि इस मामले में था, कि नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, तो ट्रिब्यूनल चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करेगा। इस मामले में चुनाव एक डबल सीट निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था और एक अभिन्न संपूर्ण था। अगर इसे शून्य घोषित किया जाना था, तो ट्रिब्यूनल का पूरे चुनाव को रद्द करने का निर्णय उचित था।"

1951 के अधिनियम की धारा 100 को लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (1956 का 27) की धारा 55 (इसके बाद 1956 अधिनियम के रूप में कहा जाएगा) द्वारा संशोधित किया गया था, और "ट्रिब्यूनल चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करेगा" शब्दों के लिए संशोधन द्वारा निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे: - "ट्रिब्यूनल वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा"

श्री सिब्बल का तर्क था कि नियम 63 (1) (सी) में शुरू से ही इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने के लिए है, न कि चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करने के लिए। उस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि सुरेंद्र नाथ खोसला के मामले (5) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रासंगिक नहीं है, बल्कि यह 1951 अधिनियम की धारा 100 (1) से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसले हैं, जैसा कि 1956 अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जो नियम 63 (1) (c) के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक हैं। इस संबंध में वकील ने **आर नरसिम्हा रेड्डी और एक अन्य भूमाजी और एक अन्य (6)**[5] मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।। उस निर्णय के पैरा (32) में जो कुछ हद तक समान प्रश्न से संबंधित है, यह निम्नानुसार देखा गया था: –
"प्रतिवादी के वकील श्री बीवी सुब्रमण्यम ने आग्रह किया है कि दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव एक अभिन्न अंग है और जहां एक चुनाव को अलग रखा जाता है, पूरे चुनाव को शून्य माना जाना चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने सुरेंद्र नाथ खोसला बनाम दलीप सिंह (5) मामलें में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।उस मामले में सवाल यह था कि क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 (एल) (सी) के अर्थ के भीतर नामांकन की अनुचित अस्वीकृति थी।

सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अस्वीकृति अनुचित थी और इसलिए, इसने पूरे चुनाव को शून्य बना दिया। इस फैसले का इस मामले पर कोई असर नहीं है। इस मामले में किसी भी नामांकन की अनुचित अस्वीकृति नहीं है और उस संबंध में उत्पन्न होने वाले अनुमान उत्पन्न नहीं होंगे। यह कहा जा सकता है कि नरसिम्हा रेड्डी को उनके चुनाव की तारीख पर अधिनियम की धारा 7 (d) के कारण आंध्र प्रदेश विधान सभा में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

ऐसे मामले में ट्रिब्यूनल केवल लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। पूरे चुनाव को शून्य नहीं माना जा सकता। इसलिए, नरसिम्हा रेड्डी की विकलांगता और उनके चुनाव के शून्य होने की घोषणा दूसरे उम्मीदवार श्री मुथियाल राव को प्रभावित नहीं करेगी।"

इसी प्रकार पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के **चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह और एक अन्य बनाम जय प्रकाश**

---

[5] (6) ए.आई.आर. 1959 ए.पी. 111.

सिंह*(7)*[6] मामले में दिए गए निर्णय के पैरा *24* में निम्नलिखित भाषा में यह व्यवस्था दी गई थी कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव से संबंधित जिस उम्मीदवार का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया था, उसके अलावा लौटाए गए उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता है: —

'अंतिम सवाल यह है कि क्या न्यायाधिकरण ने चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के निर्वाचन को सही तरीके से अमान्य घोषित किया है। ट्रिब्यूनल के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र में दोनों सीटों के लिए चुनाव एक ही चुनाव था न कि दो अलग-अलग चुनाव और इसलिए, यदि उम्मीदवारों में से एक का चुनाव शून्य माना जाता है तो पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने माना कि यदि भागवत मार्मू का नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया होता, तो अन्य दो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से एक को वापस कर दिया गया होता और इसलिए यह स्पष्ट था कि भागवत मुर्मू के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित माना जाना चाहिए। इस आधार पर ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया और चंद्र शेखर प्रसाद सिंह के चुनाव को भी रद्द कर दिया। इस न्यायालय में प्रतिवादी के विद्वान वकील ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष का समर्थन किया है और सुरेंद्र नाथ खोसला बनाम दलीप सिंह *(5)* के मामले पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा है कि डबल सीट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव एक अभिन्न अंग है और यदि कार्रवाई को रद्द किया जाना है तो पूरे चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। यह देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य का यह निर्णय 1951 के अधिनियम XLIII की धारा 100 से संबंधित था क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम (1956 का XXVII) द्वारा संशोधित किया गया था। इस तथ्य के अलावा कि निर्णय नामांकन की अनुचित अस्वीकृति के मामले से निपट रहा था, धारा 100 (l) (c) जैसा कि तब थी, ने कहा कि 'ट्रिब्यूनल चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करेगा'। 1951 के अधिनियम XLIII की धारा 100, जैसा कि यह अब है, इसके कुछ पहलुओं में काफी भिन्न है। पुरानी धारा 100 (एल) (सी) को निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

धारा 100 (1) * * * *

(c)कि किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है; नहीं तो

(d) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से, ट्रिब्यूनल लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा। (केवल प्रासंगिक भागों को उद्धृत किया गया है)।

इस संबंध में उसी अधिनियम की धारा 98 पर भी ध्यान दिया जा सकता है। धारा 98 जैसा कि यह 1956 के उसी संशोधन अधिनियम द्वारा अपने संशोधन से पहले था, निम्नानुसार कहा गया है:

"एक चुनाव याचिका के परीक्षण के समापन पर ट्रिब्यूनल एक आदेश देगा-

(a) चुनाव याचिका को खारिज करना; या

(b)लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करना;या

(c) लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करना और याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना; या

(d)चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करना।

धारा 98 अब इस प्रकार है:

एक चुनाव याचिका के परीक्षण के समापन पर, ट्रिब्यूनल एक आदेश देगा-

(a) चुनाव याचिका को खारिज करना; या

(b)सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों के चुनाव को शून्य घोषित करना, या

(c)सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों के चुनाव को शून्य घोषित करना और याचिकाकर्ता या किसी अन्य

---

(7) ए.आई.आर. 1959 पटना 450.

उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना। पर्याप्त परिवर्तन खंड को हटाना है;
(d)जिसके द्वारा निर्वाचन को पूर्णतया शून्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए, मेरी राय में, 1951 के अधिनियम XLIII की धारा 98 और 100, जैसा कि वे अब हैं, इंगित करती हैं कि किसी भी लौटे हुए उम्मीदवार के किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति अपने आप में किसी अन्य उम्मीदवार या उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का एक अच्छा आधार नहीं हो सकती है। यह हो सकता है। उन्होंने गौर किया कि इस बात की जांच के लिए कोई मुद्दा नहीं बनाया गया कि क्या भागवत मुर्मू के नामांकन की अनुचित स्वीकृति से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह का चुनाव प्रभावित हुआ है। चंद्र शेखर प्रसाद सिंह के चुनाव को ऊपर उद्धृत सामान्य मुद्दों संख्या 10 और 11 पर शून्य घोषित किया गया था। ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष के बावजूद कि चंद्रशेखर प्रसाद सिंह अपने खिलाफ सुझाए गए सभी आरोपों से मुक्त थे, उनके चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया था कि दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अविभाज्य हैं। मेरी राय में, ट्रिब्यूनल ने इस प्रश्न पर खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है। यह माना जाना चाहिए कि चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के चुनाव को गलत तरीके से शून्य घोषित किया गया है।"

14. माता दीन की ओर से श्री सिब्बल द्वारा दिए गए एकमात्र तर्क के जवाब में, रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री नंद लाल ढींगरा ने टेक चंद, जे० के बुड्ढा माई और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (8) [7]के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा जताया।बुद्ध माई के मामले में टेक चंद, जे के फैसले के अनुपात की सराहना करने के लिए और इस संबंध में श्री ढींगरा की विस्तृत प्रस्तुतियों से निपटने के लिए, इस स्तर पर उसी अधिनियम के 1951 अधिनियम (1956 में इसके संशोधन से पहले) के कुछ संगत प्रावधानों से प्रासंगिक निष्कर्ष निर्धारित करना आवश्यक है, जैसा कि 1956 में संशोधित किया गया था और फिर 1961 में संशोधित के साथ-साथ पंजाब नगरपालिका अधिनियम और चुनाव नियमों के प्रासंगिक प्रावधान।

15. यह याद किया जा सकता है कि संसदीय संविधान के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में, बहुवचन-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र तब तक मौजूद थे जब तक कि उन्हें 1961 में समाप्त नहीं कर दिया गया था। 1951 के अधिनियम की धारा 63 (1) में प्रावधान था कि बहुवचन-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता के पास उतने ही वोट होंगे जितने चुने जाने वाले सदस्य हैं, लेकिन कोई भी मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं देगा। 1951 अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (1) के अनुरूप प्रावधान नगरपालिका चुनावों से संबंधित चुनाव नियमों के नियम 31 (1) में निहित है। इसमें कहा गया है कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां एक सीट अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित है, प्रत्येक मतदाता के पास दो वोट होंगे, लेकिन कोई भी मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं देगा। इन प्रावधानों का प्रभाव यह है कि एक निर्वाचक अपने दोनों मत आरक्षित सीट के उम्मीदवारों के पक्ष में या अपने दोनों मत सामान्य सीट के उम्मीदवारों के पक्ष में या एक मत आरक्षित सीट के उम्मीदवार के पक्ष में और दूसरा सामान्य सीट के उम्मीदवार के पक्ष में डाल सकता है जब तक कि वह अपने दोनों मत एक ही उम्मीदवार के पक्ष में न डाले। जहां तक संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का संबंध है, दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम (1961 का I) की धारा 3 के संचालन के तहत बहुवचन-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था। नतीजतन, 1961 के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 40 द्वारा 1951 के अधिनियम में संशोधन किए गए। 1961 के अधिनियम 40 की धारा 14 में कहा गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 63 को हटा दिया जाएगा।

16. इसी प्रकार धारा 54, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बहुवचन-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिणामों की घोषणा करने के तरीके का प्रावधान था, को 1961 के अधिनियम 40 की धारा 12 के प्रचालन द्वारा 1951 के

---

(8) 1967 पी.एल.आर. 974

अधिनियम से हटा दिया गया था। चुनाव नियमों का संबंधित नियम 40 (बी) जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 1951 अधिनियम की धारा 54 की पूर्ववर्ती उप-धारा (4) के समान है और जो निम्नलिखित शर्तों में है आज तक बरकरार है क्योंकि पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत डबल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को अब तक समाप्त नहीं किया गया है: —

"40 (बी) एक निर्वाचन क्षेत्र में जहां भरी जाने वाली सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक या अधिक सीटें शामिल हैं (इसके बाद "आरक्षित सीटों" के रूप में संदर्भित) वे उम्मीदवार, जो आरक्षित सीटों को भरने के लिए चुने जाने के योग्य होने के नाते, आरक्षित सीटों को भरने के लिए विधिवत चुने जाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में वैध वोट प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पहले घोषित किया जाएगा, और फिर शेष उम्मीदवारों में से जिन्होंने शेष सीटों को भरने के लिए विधिवत निर्वाचित होने के लिए सबसे अधिक वैध वोट प्राप्त किए हैं, घोषित किए जाएंगे।

यद्यपि 1951 के अधिनियम की धारा 54 (4) के तहत एक वैधानिक चित्रण दिया गया था और चुनाव नियमों के नियम 40 (बी) के तहत ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया था फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों प्रावधान बिल्कुल उसी तरह से काम करना था। 1951 अधिनियम की धारा 54(4) के तहत चित्रण निम्नलिखित शब्दों में था -

" उदाहरण- एक निर्वाचन क्षेत्र में चार सीटों को भरने के लिए एक चुनाव में, जिनमें से दो आरक्षित हैं, छह उम्मीदवार A, B, C,D, E और F हैं, और वे अवरोही क्रम में वोट सुरक्षित करते हैं, A सबसे बड़ी संख्या हासिल करता है, B, C और D आरक्षित सीटों को भरने के लिए चुने जाने के योग्य होते हैं, जबकि A, E और F इतने योग्य नहीं हैं। निर्वाचन अधिकारी पहले दो आरक्षित सीटों को भरने के लिए B और C को विधिवत निर्वाचित घोषित करेंगे, और फिर शेष दो सीटों को भरने के लिए A और D (A और E नहीं) घोषित करेंगे।

नियम 40 (b) में निहित प्रावधान का प्रभाव यह है कि आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने वालों में से सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले व्यक्तियों को आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाना है और शेष उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों को सामान्य सीट के लिए चुनाव घोषित करने के लिए एक साथ विचार करना होगा, चाहे वह आरक्षित सीट या सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हो।

17. दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में, जिसके साथ हम चिंतित हैं, जबकि मोहन लाल, उदमी राम, घासी राम, बनवारी लाल, लालजी राम और भगवती प्रसाद ने आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा, माता दीन अपीलकर्ता नंबर 2 और अन्य उत्तरदाताओं ने सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ा। मोहन लाल ने सबसे अधिक वोट हासिल किए, यानी 582, और उन्हें आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। माता दीन ने शेष सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट (515) हासिल किए थे, जिन्हें सामान्य सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। सामान्य सीट के लिए मुकाबला उस सीट के उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आरक्षित सीट के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए सामूहिक रूप से खुला होना था।

18. जबकि 1951 के अधिनियम की धारा 100 की उप-धारा (1) में "चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित करेगा" शब्दों को 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, "लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा", पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 255 में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है जिसके तहत प्रावधान जारी है :-

"आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर (धारा 254 के तहत जांच के समापन पर) राज्य सरकार या तो उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करने या चुनाव को शून्य घोषित करने के आदेश पारित करेगी और इस तरह के आदेश को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। "

इस प्रावधान से पता चलता है कि नगरपालिका चुनाव में डाले गए मतों की गिनती के बाद, अधिनियम की धारा

255 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की जानी है। घोषणा या तो यह हो सकती है कि एक उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हो गया है या यह कि एक विशेष चुनाव शून्य है। जहां तक तदनुरूपी सांविधिक उपबंधों के वाक्यांशविज्ञान का संबंध है, 1956 के अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व 1951 अधिनियम की धारा 100(1) में प्रयोग किया गया था, अर्थात् चुनाव को निरस्त करने के लिए, नगरपालिका अधिनियम की धारा 255 में पाया जाना चाहिए, न कि वह जो केवल लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने तक ही सीमित है, जो अब संशोधित धारा 100(1) में होता है।

19. श्री सिब्बल ने नियम 63 के उप-नियम 1 के प्रासंगिक भाग की भाषा और चुनाव नियमों के नियम 69 में निहित प्रावधान पर भरोसा करते हुए कहा कि नगरपालिका चुनाव में दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में भी, यह अकेले उस उम्मीदवार का चुनाव है जिसका नामांकन पेपर गलत तरीके से स्वीकार किया गया था जिसे दरकिनार किया जाना चाहिए और उस वार्ड से पूरा चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता है। नियम 63 (1) के प्रासंगिक भाग को इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। यह आयोग को यह रिपोर्ट करने का अधिकार देता है कि "लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य माना जाएगा"। इसी तरह, नियम 69 में कहा गया है कि जब चुनाव नियमों के तहत किसी जांच के परिणामस्वरूप किसी उम्मीदवार का चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है, तो आयुक्त या पंजाब सरकार, जैसा भी मामला हो, निर्देश देगी कि एक नया चुनाव कराया जाएगा। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि नियम 63 (1) और 69 की शब्दावली मामले को सुरिंदर नाथ खोसला के मामले (5) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे से बाहर ले जाएगी, क्योंकि यह निर्णय असंशोधित धारा 100 (1) के संबंध में दिया गया था, जिसमें पूरे चुनाव को शून्य घोषित करने की परिकल्पना की गई थी। हम एक से अधिक कारणों से श्री सिब्बल के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव के नियम पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत तैयार किया गए है और इसे नगरपालिका अधिनियम के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, नियमों को अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि किसी स्थिति में, यह संभव नहीं है, तो नियम रास्ता देंगे और अधिनियम प्रबल होगा। संविधियों की व्याख्या के इन सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम यह कहना चाहते हैं कि आयुक्त द्वारा नियम 63(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणा धारा 255 के अनुसार होनी चाहिए। नियम 69 के तहत आयुक्त या सरकार द्वारा निर्देशित पुन: चुनाव, जैसा भी मामला हो, पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव होना चाहिए।

20. प्रश्न के उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव कैसे होता है। मैं पहले ही निर्वाचन नियमावली के नियम 40(ख) का उल्लेख कर चुका हूं जिसमें ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करने के तरीके के संबंध में प्रावधान है। धारा 54 (4) के तहत वैधानिक चित्रण (जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है) एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस तरह के चुनाव कैसे होते हैं, इसका एक और उदाहरण इसी मामले से मिलता है। इस बात की सराहना करने के लिए, मैं इस चुनाव में केवल कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों का उल्लेख करूंगा।

(1) मोहन लाल अपीलकर्ता नंबर 1 आरक्षित सीट है; ... 582
(2) माता दीन, अपीलकर्ता नंबर 2 जनरल बैठक; ... 515
(3) रघुबीर सिंह, प्रतिवादी नंबर 19, सामान्य सीट; ... 352
(4) लाजपत राय, प्रतिवादी नं. 14, सामान्य सीट; ... 345
(5) उदमी राम, प्रतिवादी नं. 7, आरक्षित सीट; ... 280
(6) घासी राम, प्रतिवादी नं. 3, आरक्षित सीट; ... 159

यदि निर्वाचन अधिकारी ने गलत आदेश पारित नहीं किए थे और मोहन लाल को आरक्षित सीट के लिए उम्मीदवार

मानने से इनकार कर दिया था, तो भी उन्हें वी. वी गिरि बनाम डी. सूरी डोरा और अन्य (9)[8] मामलें में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती थी।यह किसी का मामला नहीं है कि उस घटना में उसका भाग्य क्या होना था। किसी भी स्थिति में, उन्हें आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता था। उस स्थिति में अगर मोहन लाल को 582 वोट भी मिलते, तो यह उदमी राम ही होते जिन्हें 280 वोट मिलते, जिन्हें पहले आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता और फिर अगर मोहन लाल को 582 वोट मिलते, तो उन्हें सामान्य सीट के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता, लेकिन माता दीन को किसी भी सीट के लिए निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह भी सुझाव नहीं दिया गया है कि मोहन लाल किसी भी स्तर पर सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। न तो रिट याचिका पर अपनी वापसी में और न ही लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के अपने आधार पर मोहन लाल ने दावा किया है कि उन्हें सामान्य सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए था। यदि मोहन लाल को आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं पाया गया है, तो माता दीन का चुनाव, जिन्होंने केवल सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ा था, संभवतः बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

21. एक तीसरा उदाहरण अब एक अनुमानित आधार पर चुनाव से पहले के उदाहरण को देखा जा सकता है। मान लीजिए कि विवाद में चुनाव के लिए प्रतियोगियों जिनके नाम पहले ही ऊपर दिए गए हैं, उन्हें सुरक्षित करना था: –

(i) मोहन लाल	(आरक्षित सीट);	300 वोट
(ii) उदमी राम	(आरक्षित सीट);	290
(iii) माता दिन	(सामान्य सीट);	280
(iv) रघुबीर सिंह	(सामान्य सीट);	275
(v) लाजपत राय	(सामान्य सीट);	270
(vi) घासी राम	(आरक्षित सी) ;	265

यदि उपर्युक्त सभी उम्मीदवार योग्य थे, तो मोहन लाल को आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा, और उदमी राम को सामान्य सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि चुनाव के बाद, मोहन लाल को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और बाकी चुनाव को बरकरार रखा जाता है, तो उदमी राम को आरक्षित सीट के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा, और माता दीन सामान्य सीट के लिए चुने जाएंगे। इन चित्रों और अन्य जिन पर काम किया जा सकता है ,के अवलोकन का परिणाम यह दिखाते हैं कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के हिस्से को बनाए रखना असंभव है जब तक कि इसके परिणाम घोषित करने का तरीका नियम 40 (बी) में प्रदान किए गए पैटर्न पर है।

22. यह प्रतीत होता है कि यह विवाद अप्रत्यक्ष रूप से वी.वी. गिरि बनाम डी. सूरी डोरा और अन्य (9) मामलें में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा सुलझाया गया था। वह मामला 1957 में हुए आम चुनावों से संबंधित है, यानी 1956 के अधिनियम द्वारा धारा 100 के संशोधन के बाद और बहुवचन-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के उन्मूलन से

---

(9) ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1318.

पहले। बहुमत के निर्णय द्वारा, उस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय दिया गया था -

"अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने का हकदार है और उस उद्देश्य के लिए वह निर्धारित घोषणा कर सकता है और उसे करना चाहिए; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि वह आरक्षित सीट के लाभ का दावा करता है और उस संबंध में वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप है, इसलिए उसे सामान्य सीट के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव पूरे निर्वाचन क्षेत्र से है, न कि दो अलग-अलग सीटों के संदर्भ में, तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी जब उन्होंने प्रतिवादी 1 को सामान्य सीट के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किया था।

एक बार जब यह पता चल जाता है कि जैसा कि वास्तव में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए और यहां तक कि इस मामले की परिस्थितियों में भी, कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव एक अभिन्न अविभाज्य संपूर्ण था, माता दीन अपीलकर्ता का चुनाव मोहन लाल अपीलकर्ता के चुनाव के साथ इस निष्कर्ष पर होना चाहिए कि मोहन लाल आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।

23. श्री नंद लाल ढींगरा ने निर्वाचन न्यायाधिकरणों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया, जिनका संदर्भ इस स्तर पर विद्वान वकील को भी दिया जा सकता है। जगन्नाथ बनाम पांडुरंग और अन्य (10) [9]में चुनाव न्यायाधिकरण, जबलपुर ने माना कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जिसमें एक सामान्य सीट और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक सीट है, चुनाव सामान्य सीट और आरक्षित सीट के लिए दो अलग-अलग चुनाव नहीं हैं, बल्कि एक अविभाज्य चुनाव है जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी सामान्य सीट के चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 1951 के अधिनियम की धारा 100 (1) (सी) में 'चुनाव' शब्द की व्याख्या इस तरह के मामले में की जानी चाहिए कि यह दोनों सीटों के लिए चुनाव है और यदि दोनों में से किसी एक के लिए नामांकन की अनुचित अस्वीकृति है व दोनो सीटों के चुनाव को प्रभावित किया है, तो दोनों सीटों के लिए चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह धर्मवीर बनाम भाला राम और अन्य (11)[10] में बामाला के चुनाव न्यायाधिकरण ने कहा कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट के साथ-साथ सामान्य सीट के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूरे चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए यदि किसी एक सीट के लिए चुनाव शून्य पाया जाता है। इस संबंध में श्री ढींगरा द्वारा जिस अंतिम मामले का संदर्भ दिया गया था, वह निर्वाचन अधिकरण, नागपुर के मोरेश्वर पराश्रम बनाम चतुर्हुज विट्ठलदास जसानी और अन्य (12)[11] में निर्वाचन अधिकरण का निर्णय है।। वहां भी ट्रिब्यूनल ने कहा कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में यदि आरक्षित सीट के लिए नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है, तो सामान्य सीट सहित पूरे चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

24. हमने ऊपर कहा है कि दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव "एक चुनाव" था और इसे दो अलग-अलग चुनावों के बराबर नहीं किया जा सकता है। आरक्षित सीट पर मोहन लाल का चुनाव सही तरीके से रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने नियम 11 (2) के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं किया था। उसी चुनाव का दूसरा भाग, अर्थात, सामान्य सीट से संबंधित भाग को अभिन्न पूरे से अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए, चुनाव स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले के इस दृष्टिकोण में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

---

(10) IV E.L.R. 167

(11) VII E.L.R 64

(12) VII E.L.R 428

25. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य बिंदु नहीं दिया गया है, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है। वकील की फीस 100 रुपये।

मेहर सिंह, सी० जे०-मैं सहमत हूं।[12]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा

एन०के०एस